सुविचार
खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दु:ख होता है।
–चाणक्य

RNI No. RAJHIN/2001/05699
जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

हैलो सरकार

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-256 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, बुधवार 20 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

NTA में बड़ा फेरबदल, चार अधिकारियों की हुई नियुक्ति, संभालेंगे अलग-अलग जिम्मेदारी

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। देशभर में NEET पेपर लीक विवाद के बाद अब National Testing Agency यानी NTA अपनी पूरी व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई है। लगातार उठ रहे सवालों और छात्रों के बीच बढ़ती नाराजगी के बाद एजेंसी ने बड़े प्रशासनिक और तकनीकी बदलावों की शुरुआत कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर हङ्ग ने कई अहम सुधारों का ऐलान किया है। एजेंसी ने साफ किया है कि अब परीक्षा सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हङ्ग में चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें दो संयुक्त सचिव लेवल और दो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। इनकी जिम्मेदारी एजेंसी में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार लागू करने और पूरी व्यवस्था की निगरानी करना होगी।

नई भर्ती भी की जाएगी

नई नियुक्ति के साथ ही पहली बार टेक्निकल, फाइनेंस औरएचआर के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती भी निकाली गई है। NTA ने Chief Technology Officer (CTO), Chief Finance Officer (CFO) और General Manager-HR जैसे बड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और आवेदन की अंतिम तारीख नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिन बाद तक रखी गई है।

जानें डिटेल्स

इन बदलावों में सबसे ज्यादा चर्चा ष्टञ्जह्र पद को लेकर हो रही है। अब परीक्षा प्रणाली की पूरी टेक्निकल सुरक्षा एक सीनियर टेक्निकल अधिकारी की निगरानी में रहेगी। यह अधिकारी ्रढ्ढ आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और प्रश्नपत्र सुरक्षा जैसे सिस्टम को विकसित करेगा। एजेंसी ने कहा है कि अब प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसकी प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट तक हर स्तर पर टेक्निकल सुरक्षा लागू की जाएगी। साथ ही एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान और फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भी और मजबूत किया जाएगा।

आपको बता दें कि NTA हर साल देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है। ऐसे में हाल के विवादों ने एजेंसी की विश्वसनीयता पर बड़ा असर डाला है। अब सरकार और हङ्ग दोनों यह संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाएगा।

जल संकट और गैस मुद्दे पर विपक्ष फैला रहा भ्रम-मदन राठौड

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारें लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद राजस्थान में स्थायी जल व्यवस्था विकसित नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जोधपुर सहित कई क्षेत्रों में पानी की स्थायी समस्या का समाधान नहीं कर पाए।राठौड़ ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार जल संकट के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है और घर-घर पानी पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया कि भाखड़ा बांध से क्लोजर आने के कारण कुछ समय के लिए जल आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, जिनके समाधान के लिए प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यालय का घेराव करने से पहले कांग्रेस नेताओं को आत्ममंथन

करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन घटनाओं को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है और यह कांग्रेस से जुड़े लोगों का ही कारनामा है।

गैस और पेट्रोल संकट के मुद्दे पर राठौड़ ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि गल्फ देशों में तनावपूर्ण हालात और युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है।

उन्होंने कहा कि हार्मुज मार्ग से भारतीय पोत सुरक्षित आवाजाही कर रहे हैं और देशहित में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मितव्ययिता अपनाने और वाहन शेयरिंग जैसी अपील समाजहित और राष्ट्रहित में है, इसे विपक्ष द्वारा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

इससे पहले राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ता रेना द्वारा भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए परिंडा लगाने की सराहना की। उन्होंने प्रदेशवासियों से पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करने और अधिक से अधिक परिंडे लगाने की अपील भी की।

इवेंटमैनेजमेंट से लकवा ग्रस्त सरकार, प्रदेश में आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त-डोटासरा

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य और केन्द्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अनियंत्रित मंहगाई, नीट पेपर लीक घोटाला और राज्य की स्वास्थ्य व शिक्षा प्रणाली के पूर्ण पतन जैसे गम्भीर मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार केवल इवेंटमैनेजमेंट और नौटंकी के सहारे चल रही है। आर्थिक संकट और ईंधन की कमी

डोटासरा ने आसमान छूती मंहगाई पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि पेट्रोल की कीमतें लगभग 110 तक पहुँच गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन की सख्त राशनिंग की जा रही है, जहाँ आम नागरिकों को केवल 1000 से 1500 का ईंधन मिल रहा है और उद्योगों के लिये यह सीमा एक लाख है। देश में केवल 9 से 10 दिन का ईंधन भण्डार बचा है। उन्होंने आगाह किया कि यदि यही हालात रहे तो अगले 10 से 15 दिनों में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जिससे उद्योग और वाहनों का संचालन ठप्प हो जायेगा।

नीट घोटाला और युवाओं से धोखा

केन्द्र पर निशाना साधते हुये, उन्होंने नीट परीक्षा घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए के अधिकारी 2019 से कोचिंग माफियाओं के साथ मिलीभगत कर पेपर बेच रहे हैं। यह 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बा कर रहा है और देश में फर्जी डॉक्टर बना रहा है। इस अन्याय के खिलाफ 21 मई को भाजपा कार्यालय का विशाल घेराव और प्रदर्शन किया जायेगा।

प्रशासनिक लकवा और नौकरशाही का राज

डोटासरा ने सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करते हुये बताया कि कर्मचारियों को मई और अप्रेल माह का वेतन नहीं मिला है। 70 साल के इतिहास में पहली बार बिना वित्तीय स्वीकृति के जून का महीना आ रहा है। वित्त विभाग ने पीडब्ल्यूडी सडकों की 3000 करोड़ की घोषणाओं को अवैध रूप से डीएमएफटी फंड से वित्त पोषित करने के निर्देश दिये हैं, जो केवल खनन् प्रभावित क्षेत्रों के लिये हैं। उन्होंने मंत्रियों की नौटंकी का कड़ा मजाक उड़ाया।

स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था खस्ताहाल

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। डोटासरा ने बताया कि पहले मिलने वाली 750 मुफ्त दवाईयों में से अब 50 भी मुफ्त नहीं मिल रही है। निजी अस्पतालों के 3000 करोड़ बकाया पड़े हैं। सरकार ने कोटा में हुई मौतों के प्रति भी घोर उदासीनता दिखाई है। शिक्षा पर स्वयं राज्यपाल ने भी शिक्षा के गिरे स्तर, खाली विश्वविद्यालयों और फर्जी डिग्रियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है।

केंद्र सरकार से समन्वय कर खनन से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय में पूरा करें-सीएम भजनलाल शर्मा

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है तथा प्रदेश में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। हमारी सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे में विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र से समन्वय करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करें। जिससे खनन क्षेत्र से संबंधित कार्य तय समय में पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की गरिमामयी उपस्थिति में खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स प्रदेश में बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में लगभग 725 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई वृत्ताकार/अर्धवृत्ताकार आग्नेय चट्टानों की संरचना है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिवाना ग्रेनाइट में रेयरअर्थ एलिमेंट एवं हेवी रेयरअर्थ एलिमेंट उपलब्ध है। साथ

ही, आधुनिक तकनीकी एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इसका राष्ट्रीय महत्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं, इस संबंध में खान विभाग एवं संबंधित जिला कलक्टर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें, जिससे काम में तेजी आ सके। जीएसआई द्वारा प्रदेश में चिन्हित साइट्स की जानकारी राज्य से हो साझा

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राज्य में चिन्हित एवं अन्वेषित साइट्स की जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करें, जिससे संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त भूमि का अन्यत्र प्रयोजन के लिए आवंटन नहीं हो। उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ गति देने के निर्देश दिए और कहा कि जिन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, वहां पर शीघ्र ही उत्पादन कार्य शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के लिए खान विभाग के अधिकारी नियमित बैठक कर कार्य योजना बनाएं, इससे खनन कार्य में भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा।

प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों से देश में खनन क्षेत्र में हुआ व्यापक सुधार

केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अन्वेषण, नीलामी और उत्पादन प्रक्रियाओं में गति आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का बड़ा भण्डार उपलब्ध है। रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का सामर्थ्य राजस्थान में है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रो-एक्टिव अप्रोच से राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश अनुकूल वातावरण तथा पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय से खनन से जुड़े सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान करें, जिससे निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि हो।

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कोल इंडिया

आरवीयूएनएल संयुक्त उपक्रम, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, डीएमएफ फंड, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां, खनिज ब्लॉक के शीघ्र संचालन, राज्य में संचालित विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं खनिज अन्वेषण गतिविधियां तथा प्रदेश से संबंधित खनन मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों, केंद्र से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रतापगढ़ सड़क घोटाला-एसीबी ने PWD के 3 पूर्व अधिशाषी अभियंताओं और संवेदक को किया गिरफ्तार

हैलो सरकार न्यूज

कोटा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 13 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग (क्कङ्ख्नष्ठ) के तीन पूर्व अधिशाषी अभियंताओं (एक्सियन) और एक ठेकेदार (संवेदक) को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (प्रतापगढ़) के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजने के आदेश जारी किए हैं।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार -

सायरमल मीणा (निवासी सीकर) = तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण, खंड प्रतापगढ़।

एन.एल. परमार (निवासी बांसवाड़ा) = तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण खंड, बांसवाड़ा।

गिरधारी लाल वर्मा (निवासी चित्तौड़गढ़) = तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. द्वितीय पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़।

विनोद केडिया (निवासी जयपुर) =संवेदक एवं प्रोपराइटर, मेसर्स जय बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी।

घटिया निर्माण और बिना काम किए उठाए बिल= ?11.78 लाख का घोटाला

एसीबी रेंज कोटा के प्रभारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि वर्ष 2013 में प्रतापगढ़ जिले में %प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना% के तहत तीन संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया था = लेवापाड़ा संपर्क सड़क, हीरापाड़ा संपर्क सड़क, जापा कॉलोनी संपर्क सड़क।

इन सड़कों के निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके कारण सड़कें बनते ही टूटने लगी थीं। इसके अलावा अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलीभगत कर कार्य पूरा होने से पहले ही उसे कागजों में पूर्ण दिखा दिया और झूठे बिल पेश कर भुगतान उठा लिया। कुछ कार्य तो ऐसे थे जो धरातल पर हुए ही नहीं, लेकिन उनका भी भुगतान उठा लिया गया।

2013 में औचक निरीक्षण के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

इस घोटाले की शिकायत मिलने पर 19 जुलाई 2013 को एसीबी चौकी प्रतापगढ़ द्वारा सड़कों की विधिवत आकस्मिक चेकिंग (औचक निरीक्षण) की गई थी। इसके बाद 18 नवंबर 2013 को एसीबी में प्रकरण संख्या 503/2013 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी

मामले के अनुसंधान अधिकारी एवं एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार द्वारा की गई गहन जांच में सामने आया कि तीनों अभियंताओं और ठेकेदार विनोद केडिया ने आपसी मिलीभगत कर राज्य सरकार को 11,78,752 रुपये की सीधी आर्थिक हानि पहुंचाई है। अपराध पूरी तरह प्रमाणित पाए जाने के बाद एसीबी मुख्यालय ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने का निर्णय लिया, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा तीनों अभियंताओं के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति (प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन) जारी की गई।

अभियोजन स्वीकृति मिलते ही एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 18 मई 2026 को चारों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया और आज 19 मई को प्रतापगढ़ की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

कहीं प्यास से मवेशियों की मौत, कहीं टैंकरों पर निर्भर लोग; कई शहरों में प्रदर्शन

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में पेयजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश के 315 शहरों और कस्बों में से 205 इलाके इस समय जल संकट की चपेट में हैं। इनमें 30 शहरों और कस्बों में तीन दिन में एक बार, जबकि 24 स्थानों पर चार दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। राजधानी जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों में भी पाइपलाइन के टेल एंड क्षेत्रों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन आकस्मिक कार्यों हेतु 210.71 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन के लिए 105 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने प्रत्येक जिला कलेक्टर को एक-एक करोड़ रुपये का इमरजेंसी फंड भी उपलब्ध कराया है, ताकि जहां जलापूर्ति बाधित हो वहां तत्काल राहत कार्य कराए जा सकें। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया

कि प्रदेश के 41 जिला सर्किलों में जल जीवन मिशन के कार्यों के संचालन और निगरानी के लिए प्रत्येक जिले को 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

वर्तमान में मकराना, लाडनूं, बांदीकुई, दौसा, बालोतरा और भोपालगढ़ में पेयजल की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। सरकार का दावा है कि जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर सप्लाई और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बाड़मेर में पानी के अभाव में गायों की मौत के मामले सामने आए हैं। कई शहरों और गांवों में लोगों ने जल संकट को लेकर प्रदर्शन भी किए।

बाड़मेर जिले के देरासर गांव में पिछले कुछ दिनों में 10 से अधिक गायों की मौत होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की मुख्य पेयजल आपूर्ति स्रोत बाड़मेर लिफ्ट कैनाल करीब एक महीने से बंद है। भीषण गर्मी के बीच हैंडपंप और भूजल स्रोत भी सूख चुके हैं। रामदियों की बस्ती क्षेत्र से सामने आए वीडियो में सूखे जलाशय के पास गायों के शव दिखाई दिए। एक गाय खाली पानी की टंकी में मृत मिली।

जयपुर बना भक्तिमय, गीता-भागवत और मीरा कथा में उमड़ी भीड़

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। जयपुर में अधिकमास के दौरान मंदिरों और कथा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के अलग-अलग इलाकों में भागवत कथा, रामकथा और मीरा चरित्र जैसे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यहां लोग सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन और आध्यात्मिक सीख भी ले रहे हैं।

जयपुर के मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

अधिकमास को सनातन परंपरा में बेहद पुण्यदायी माना जाता है। यही कारण है कि इस बार जयपुर में धार्मिक आयोजनों की मानो बाढ़ सी आ गई है। शहर के मंदिरों, धर्मशालाओं और कथा स्थलों पर सुबह से लेकर देर रात तक भजन, कथा और सत्संग का माहौल बना हुआ है। कहीं श्रीमद्भागवत कथा हो रही है तो कहीं रामकथा और मीरा चरित्र का रसपान कराया जा रहा है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आयोजकों ने विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बैठने से लेकर पार्किंग और पेयजल तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

भगवद्गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्ग है

जयपुर के चौड़ा रास्ता क्षेत्र स्थित गोवर्धननाथ मंदिर में चल रही भागवत कथा में कथावाचकों ने भगवान श्रीकृष्ण के संदेशों को सरल भाषा में समझाया। कथा के दौरान कहा गया कि भगवद्गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान है।

वक्ताओं ने बताया कि गीता का हर श्लोक इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, कर्म और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कथा में यह भी कहा गया कि श्रीकृष्ण की वाणी आज के तनावपूर्ण जीवन में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है।

मीरा की भक्ति ने श्रद्धालुओं को किया भावुक

शहर के कई स्थानों पर आयोजित मीरा चरित्र कथा में भक्तों ने मीरा बाई के कृष्ण प्रेम और त्याग की गाथाएं सुनीं। कथा के दौरान जब मीरा के भजन गाए गए तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

कथावाचकों ने कहा कि मीरा ने समाज की बंदिशों से ऊपर उठकर भक्ति को चुना और यही संदेश आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि अपने विश्वास और सत्य के लिए डटे रहें।

अहंकार और मनमानी विनाश का कारण

गलता गेट क्षेत्र में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में वक्ताओं ने अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया। कथा में शिव-पार्वती विवाह और सती चरित्र के प्रसंगों के माध्यम से समझाया गया कि जब व्यक्ति मर्यादा और विनम्रता छोड़ देता है, तब उसका पतन तय हो जाता है।

धर्मगुरुओं ने लोगों से परिवार और समाज में प्रेम, संयम और संस्कार बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार और सोच में भी दिखना चाहिए।

क्यों खास माना जाता है अधिकमास?

हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग हर तीन साल में एक बार अधिक मास आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में दान, पूजा, जप, तप और कथा श्रवण का विशेष फल मिलता है।

देशभर में इस दौरान मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। वृंदावन, उज्जैन, नाथद्वारा, अयोध्या और जयपुर जैसे धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

युवाओं में भी बढ़ रही धार्मिक रुचि

इस बार एक खास बात यह देखने को मिल रही है कि धार्मिक आयोजनों में युवाओं की भागीदारी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर कथा, भजन और आध्यात्मिक संदेशों के छोटे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई युवा गीता और भागवत के श्लोक सीखने में रुचि दिखा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि तेज भागदौड़ और मानसिक तनाव के दौर में लोग आध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। यही वजह है कि कथा पंडालों में अब केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि कॉलेज छात्र और नौकरीपेशा युवा भी दिखाई दे रहे हैं।

भक्ति के साथ सामाजिक संदेश भी

इन धार्मिक आयोजनों में केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि समाज सुधार के संदेश भी दिए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार में संस्कार और महिलाओं के सम्मान जैसे विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

अधिक मास के इस माहौल ने जयपुर को पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंग दिया है। मंदिरों से उठते भजन, कथा स्थलों पर उमड़ती भीड़ और कृष्ण नाम की गूंज यह बता रही है कि आधुनिक जीवन की आपाधापी के बीच भी लोगों की आस्था आज उतनी ही मजबूत है।

कृषि आधारित उद्योग है मधुमक्खी पालन

(लेखक - संजय गोस्वामी)

20 मई26 विश्व मधुमक्खी दिवस पर विशेष)

विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना हैमधुमक्खी एक सामाजिक कीट का सबसे अच्छा उदाहरण है जो शहद इकट्ठा करती है और अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। यह कीट हाइमनोप्टेरा गण के एपिस परिवार के अंतर्गत आता है। भारत में मधुमक्खियों की तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं, भारतीय मधुमक्खी (एपिस इंडिका), रॉक शहद मधुमक्खी (एपिस डोरसोटा) और छोटी शहद मधुमक्खी (एपिस फ्लोरिया)। एक विदेशी शहद मधुमक्खी (एपिस मेलिफेरा) जिसे इटालियन या यूरोपीय शहद मधुमक्खी कहा जाता है, अब भारत में स्थापित हो गई है और इसका उपयोग व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए किया जा रहा है। मधुमक्खियों के प्रकार - मधुमक्खियों की उपरोक्त चार प्रजातियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है - (1) भारतीय शहद मधुमक्खी (एपिस सेराना इंडिका) - यह शहद मधुमक्खी पूरे भारत में पाई जाती है। यह पीले भूरे रंग की होती है। यह पुरानी इमारतों, जंगलों, पेड़ों की खोखली दीवारों, गुफाओं आदि जैसे अंधेरे स्थानों में 6-8 समानांतर छत्ते बनाती है। ये मधुमक्खियां स्वभाव से कोमल और शांत होती हैं और इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। मधुमक्खी पालक इन्हें प्राकृतिक घरों से पकड़ते हैं और मधुमक्खी के बक्सों में पालते हैं। यह एक उद्यमी मधुमक्खी है तथा अच्छी मात्रा में शहद एकत्रित करती है। औसतन प्रति वर्ष एक कॉलोनी से 2-3 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। (2) रॉक मधुमक्खी (एपिस डोरसाटा)- इस मधुमक्खी को भौंरा या भौंरा भी कहते हैं। यह सम्पूर्ण भारत में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊँचाई तक पाई जाती है। इसकी कॉलोनियाँ कम तापमान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ये मधुमक्खियाँ एक ही छत्ता बनाती हैं जो लगभग 1.5 से 2.1 मीटर चौड़ा तथा 0.6 से 1.2 मीटर लंबा होता है। इनका छत्ता आमतौर पर चट्टानों पर लटका होता है। ये मधुमक्खियाँ बहुत आक्रामक स्वभाव की होती हैं तथा परेशान करने पर मनुष्यों का पीछा कर उन पर हमला कर देती हैं। ये बड़ी मात्रा में शहद एकत्रित करती हैं। ये अपना काम सुबह जल्दी शुरू कर देती हैं। प्रति वर्ष एक छत्ते से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होता है। शहद आमतौर पर छत्ते के अगले भाग में मिलता है। (3) छोटी मधुमक्खी -एपिस फ्लोरिया) - यह मधुमक्खी पूरे देश में पाई जाती है लेकिन समुद्र तल से 335 मीटर की ऊंचाई पर बहुत कम पाई जाती है। यह बार-बार अपना स्थान बदलती रहती है तथा इसकी कॉलोनी एक छत्ते पर 5 महीने से अधिक नहीं रहती। यह मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है जिसका आकार हथेली के बराबर होता है। यह अपना छत्ता शाखाओं, बाड़ों, पेड़ों, गुफाओं, घरों की चिमनियों, खाली बक्सों, लकड़ियों के ढेर आदि पर बनाती है। इसकी रानी सुनहरे भूरे रंग की होती है। मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित उद्योग है, जिसकी जानकारी बहुत सरल है। इसमें लागत कम, आमदनी अधिक तथा कम समय में अधिक लाभ प्राप्त होता है। गांवों में आर्थिक विकास के लिए मधुमक्खी पालन से अच्छा कोई घरेलू रोजगार नहीं है। जानकारी की सहजता के कारण कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कुशलता से कर सकता है। गरीब, भूमिहीन भी 5 से 10 मधुमक्खी बक्सों की कम पूंजी से यह व्यवसाय शुरू कर 3 साल के भीतर 50-100 बक्सों का मालिक बन सकता है तथा मधुमक्खियां, मोम व शहद बेचकर सालाना लाखों रुपए कमा सकता है। चूंकि इस काम में ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं होती, इसलिए ग्रामीण महिलाएं और बच्चे अपने घरेलू कामों के साथ इसे आसानी से कर सकते हैं। चूंकि इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए बेरोजगार युवा भी इसे अपने रोजगार का जरिया बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन से गांवों में मधुमक्खी के बक्से और अन्य उपकरण बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के लिए यह एक बेहतरीन घरेलू उद्योग है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं, जिनके परिवार में एक मां मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देती है, दूसरा सदस्य नर मधुमक्खी होता है जो सिर्फ गर्भाधान की प्रक्रिया करता है। ये आकार में बड़ी, डंक रहित और पेट के आखिरी हिस्से पर घने बाल वाली होती हैं और काले रंग की होती हैं। तीसरा सदस्य श्रमिक मधुमक्खी होती है, जो संख्या में सबसे ज्यादा होती है। एक अच्छी मधुमक्खी कॉलोनी में इनकी संख्या 30000-500000 तक हो सकती है। ज्यादातर काम श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। अंडे से रानी

को वयस्क बनने में 15-16 दिन, श्रमिक मधुमक्खी को 20-21 दिन और नर मधुमक्खी को 23-24 दिन लगते हैं। वयस्क होने के लगभग तीन सप्ताह की आयु तक श्रमिक मधुमक्खी घर के अन्दर के कार्य जैसे सफाई, रानी और बच्चों को खिलाना और सुरक्षा देना, छत्ते बनाना, शहद तैयार करना आदि करती है। अपना घर बनाने के लिए मधुमक्खी अपने उदर ग्रन्थियों से मोम बनाती है और अपने भोजन के लिए फूलों से रस और रस एकत्रित करती है। मधुमक्खी के सेल में दो भाग होते हैं, ब्रूड सेक्शन और शहद सेक्शन। ब्रूड सेक्शन में मधुमक्खी वंश का प्रजनन चलता है और शहद सेक्शन में शहद एकत्रित किया जाता है। ब्रूड सेक्शन में मूल वंश को रखा जाता है और आवश्यकतानुसार उसे ब्रूड चैम्बर में रखा जाता है और फ्रेम में मोमी अटैचमेंट लगाकर सुपर किया जाता है। इससे मधुमक्खी अपने स्वभाव के अनुसार छत्ते बनाती है। जब मधुमक्खियां छत्तों में शहद जमा कर देती है और लगभग तीन चौथाई सेल पर कैप लगा देती है तो शहद निकालने वाली मशीन से छत्तों को घुमाकर शहद निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में न तो मधुमक्खियों के बच्चे मरते हैं और न ही छत्ता नष्ट होता है।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

मधुमक्खी पालन से गांवों में मधुमक्खी के बक्से और अन्य उपकरण बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के लिए यह एक बेहतरीन घरेलू उद्योग है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं, जिनके परिवार में एक मां मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देती है, दूसरा सदस्य नर मधुमक्खी होता है जो सिर्फ गर्भाधान की प्रक्रिया करता है। ये आकार में बड़ी, डंक रहित और पेट के आखिरी हिस्से पर घने बाल वाली होती हैं और काले रंग की होती हैं। तीसरा सदस्य श्रमिक मधुमक्खी होती है, जो संख्या में सबसे ज्यादा होती है। एक अच्छी मधुमक्खी कॉलोनी में इनकी संख्या 30000-500000 तक हो सकती है।

संपादकीय

मुनाफे का जानलेवा खेल

इंसानी जीवन मूल्यों में किस हद तक गिरावट आई है कि कुछ लालची लोग मुनाफे के लिये दूसरे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते। अब चाहे सुकोमल व बीमारियों के संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील छोटे बच्चे ही क्यों न हों। निस्संदेह, जीवनदायिनी दूध में मिलावट, इंजेक्शन लगे फल-सब्जी तथा नकली दवाइयों का कारोबार जैसे घातक कृत्य से मुनाफा कमाने में लगे लोगों की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। कल्पना करें कोई बीमार व्यक्ति सेहत के लिये दूध का सेवन करे और उसे रासायनिक पदार्थों से मिला दूध मिले तो वह स्वस्थ होने के बजाय बीमार ही हो जाएगा। ऐसा ही नकली-मिलावटी दवाइयों के बाबत कहा जा सकता है कि कोई बीमारियों से मुक्त होने हेतु दवा खरीदे और उसे नकली दवाइयां बेच दी जाएं। लेकिन इससे भी घातक वह कुकृत्य है जिसमें पंजाब में बायोमेडिकल कचरे की अवैध रीसाइक्लिंग से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दुखद ही है कि अस्पतालों और ब्लड बैंकों से एकत्र खतरनाक बायोमेडिकल कचरे को निर्धारित नियमों को ताक में रखकर रीसाइक्लिंग के लिये भेजा जा रहा था। जबकि सख्त नियमों के अंतर्गत प्रावधान है कि बायोमेडिकल कचरे को अनिवार्य रूप से नष्ट किया जाना चाहिए। खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि बायोमेडिकल कचरे से रिसाइकल किया गया प्लास्टिक, मेडिकल उपकरण, यहां तक कि सस्ते खिलौने बनाने वालों तक पहुंच रहा है। उल्लेखनीय है कि बायोमेडिकल कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के रूप में पाया जाता है, जो सस्ती उपलब्धता के कारण उत्पादकों की लागत कम कर देता है। वहीं कुछ उत्पादों को साफ करके फिर से बाजार में उतारने की भी आशंका है। दरअसल,जानलेवा अवैध कारोबार का खुलासा तब हुआ, जब पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक गोदाम से भारी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा बरामद किया। निश्चित ही, इस घातक खेल में ऐसे लोग भी शामिल होंगे, जो मेडिकल कचरे को नष्ट करने के बजाय चंद रुपयों के लिये उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। निस्संदेह, इस जानलेवा खेल के पीछे एक सुनियोजित सांठगांठ वाले गिरोह की भूमिका होगी। जिसके जरिये बायोमेडिकल कचरे को गोदामों से निकालकर स्क्रैप डीलरों के माध्यम से बेचा गया। पुलिस के छापे में गोदाम से खून से सने कॉटन पैड, प्रयोग की गई सिरिंज और खून के सैंपल वाली बोतलों समेत कई ऐसे मेडिकल वेस्ट मिले हैं जो घातक संक्रमण फैलाने का जरिया बन सकते हैं। कुछ लालची लोग मुनाफे के लिये यह जानलेवा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि नियामक तंत्र की मौजूदगी में ये खेल कैसे चल रहा था? उल्लेखनीय है कि पंजाब में अमृतसर, लुधियाना,मुक्तसर,मोहली, नकोदर और पठानकोट में छह बोयोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधाएं मौजूद हैं। इन सभी यूनिटों द्वारा हर दिन बीस हजार किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण किया जाता है। जिसकी निगरानी के लिये पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बारकोडिंग प्रणाली के जरिये जानकारी जुटाता है। इतना ही नहीं, कचरा ढोने वाले वाहनों की ट्रैकिंग और अन्य जानकारियां ऑनलाइन अपलोड की जाती हैं। सवाल यह उठता है कि इस अपवित्र कृत्य की कमजोर कड़ी कहां है? पुलिस सूत्रों ने इशारा किया है कि बायोमेडिकल कचरे पर मोहाली की एक अधिकृत कचरा संग्रहण कंपनी के बारकोड लगे थे। स्पष्ट है कि मानव स्वास्थ्य के लिये घातक कचरे को वैध निपटान प्रक्रिया से गुजारने के बजाय मुनाफे के लिये बाजार में बेच दिया गया।

समुद्र की बेचैनी, बाजार की गर्मी और भारत की ऊर्जा चुनौती

(लेखक-विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला')

पश्चिम एशिया संकट,तेल-गैस की बढ़ती कीमतें, उर्वरक दबाव और भारत की रणनीतिक तैयारी पर केंद्र सरकार की बड़ी तस्वीर

विश्व की राजनीति जब युद्ध,तनाव और सामरिक प्रतिस्पर्धा के रास्ते समुद्रों तक पहुँच जाती है,तब उसका असर केवल सीमाओं और कूटनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहता।उसका कोप आम आदमी की रसोई, अन्नदाता किसान के खेत,उद्योगों जगत की मशीनों और देश की अर्थव्यवस्था तक महसूस होता है।आज पूरी दुनिया कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, समुद्री मार्गों पर मंडराते खतरे और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई चिंता में डाल दिया है।ऐसे में पी आई बी ,भारत सरकार द्वारा आयोजित आज की अंतर-मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बढ़ते संकट और उससे निपटने की राष्ट्रीय तैयारी पर केंद्रित रही।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,उर्वरक मंत्रालय,नौवहन,वाणिज्य तथा वित्तीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति वर्तमान में सुरक्षित है,लेकिन वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव केवल तेल संकट नहीं,बल्कि समुद्री व्यापार,गैस आपूर्ति,उर्वरक उत्पादन, महँगाई और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा व्यापक विषय बन चुका है।भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।देश की ऊर्जा आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन चुका है ,लेकिन विडंबना यह है कि अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल भारत आयात करता है।यही नहीं, घरेलू एलपीजी की लगभग 60 प्रतिशत जरूरत भी आयात के माध्यम से पूरी होती है।इन आयातों का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर भारत पहुँचता है।इसलिए जैसे ही पश्चिम एशिया में संघर्ष या तनाव बढ़ता है,उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगता है।भारत ने समय रहते ऊर्जा सुरक्षा के लिए व्यापक रणनीतिक कदम उठाए हैं।देश के पास वर्तमान में लगभग 60 दिनों का रणनीतिक कच्चा तेल भंडार उपलब्ध है।इसके अतिरिक्त लगभग 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक तथा पर्याप्त नेचुरल गैस भंडारण भी मौजूद है।सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल,डीज़ल,एलपीजी और सीएनजी की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से कार्य कर रही है।हालाँकि सरकार की इस आश्वस्ति के बावजूद वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर भारत में दिखाई देने लगा है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत 113 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुँच गई है। कुछ माह पहले तक यही कीमत 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई थी।तेल की कीमतों में इस तेज वृद्धि ने सरकार और आम उपभोक्ता दोनों की चिंता बढ़ा दी है।कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सबसे सीधा असर पेट्रोल और डीज़ल पर दिखाई देता है।हाल के दिनों में देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगभग 3 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 97 रुपये प्रति लीटर तथा डीज़ल 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुँच गया। यह वृद्धि केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहती।परिवहन लागत बढ़ने से खाद्यान्न,फल-सब्जियों, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं।

सबसे अधिक चिंता समुद्री मार्गों को लेकर व्यक्त की गई।पश्चिम एशिया का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ विश्व ऊर्जा व्यापार की धुरी माना जाता है।दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल और बड़े पैमाने पर एलएनजी का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है।भारत के लिए यह मार्ग और भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि देश के तेल और गैस आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है।वर्तमान तनाव को देखते हुए भारत ने अपने आयात स्रोतों और समुद्री मार्गों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई है।आज भारत लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है, जबकि वर्ष 2006-07 में यह संख्या केवल 27 थी।रूस,अमेरिका,कनाडा,ब्राजील, अफ्रीकी देशों और अन्य वैकल्पिक बाजारों से आयात बढ़ाकर भारत ने पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है।सरकार के अनुसार अब लगभग 70 प्रतिशत तेल आयात वैकल्पिक मार्गों और नए स्रोतों से किया जा रहा है।यही कारण है कि संकट की स्थिति के बावजूद भारत में ऊर्जा आपूर्ति बाधित नहीं हुई।भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियाँ खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।इस संकट का प्रभाव केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है।इसका बड़ा असर उर्वरक क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है।भारत का उर्वरक उद्योग मुख्यतः नेचुरल गैस आधारित है।यूरिया उत्पादन में गैस प्रमुख कच्चा माल होती है। जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय गैस कीमतें बढ़ती हैं,वैसे-वैसे उर्वरक उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।खरीफ सीजन नजदीक होने के कारण यह चिंता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी।इसके लिए सरकार ने उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति दी जा रही है,जबकि उद्योगों को लगभग 80 प्रतिशत और उर्वरक क्षेत्र को लगभग 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जा रही है।यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि घरेलू रसोई,सार्वजनिक परिवहन और कृषि क्षेत्र पर संकट का न्यूनतम असर पड़े। सरकार ने यह भी संकेत दिए कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उर्वरक आयात की व्यवस्था की जा सकती है । सरकार ने जमाखोरी और कृत्रिम संकट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

अकर्मण्य न बनें

एक कहानी है। एक राजा था। उसे मंत्री की नियुक्ति करनी थी। वह नियुक्ति से पूर्व परीक्षा करना चाहता था। पांच-सात व्यक्ति आए। उसने सबको एक कमरे में बिठाकर कहा, आप सब यहां बैठें। मैं कमरे के बाहर ताला लगा देता हूं। जो भी ताले को खोलकर बाहर निकल आएगा, उसे मंत्री बनाऊंगा।

सबने सुना-सोचा- कितनी विचित्र परीक्षा। दरवाजा बंद। बाहर से ताला बंद और भीतर वालों से कहे कि बाहर आओ। यह असंभव है। छह व्यक्तियों ने सोचा, राजा पागल हो गया है। यह भी कोई परीक्षा होती है! दूसरे प्रकार से भी परीक्षा ली जा सकती थी। बाहर जाना कैसे संभव हो सकता है? वे हाथ पर हाथ रख बैठे रहे। कुछ पराप्रम नहीं किया। सातवां व्यक्ति अकर्मण्य नहीं था, पुरूषार्थी था।

उसने सोचा, जरूर इस शर्त में कोई रहस्य है। राजा ऐसी शर्त क्यों रखता? मुझे अपना पुरूषार्थ करना है। वह उठा। दरवाजे के पास गया। उसे जोर से ढकेला, वह खुल गया। उसने बाहर आकर राजा का अभिवादन किया। दरवाजे पर कोई ताला लगाया ही नहीं था, केवल सबको भुलावे में रखा था।

राजा जानना चाहता था कि कौन कर्मण्य है और कौन अकर्मण्य। उन्होंने सोचा, जब बाहर ताला है तब दरवाजा कैसे खुलेगा? इसी भ्रम ने उन्हें अकर्मण्य बना डाला। वे बाजी हार गए। जिसने पुरूषार्थ किया, कर्मण्यता का परिचय दिया, वह जीत गया। वह मंत्री बन गया। साधना का क्षेत्र निर्विघ्न नहीं है। उसमें अनेक भुलावे हैं। उन भुलावों से साधक यदि अकर्मण्य बन साधना को भुला देता है तो साधना से भटक जाता है।

विचार मंथन

लोकतंत्र में नागरिक कॉकरोच, न्यायपालिका ने पहचाना?

(लेखक- सनत जैन)

-असहमति और दमनकारी कानूनों पर उठते सवाल

देश में पिछले कुछ वर्षों में आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और असहमति की आवाज़ों को शासन और प्रशासन द्वारा कठोरता के साथ दबाया जा रहा है। आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठी डंडे, अश्रु गैस के बाद अब कठोर कानूनी धाराओं का उपयोग शुरू कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में एनएसए जैसी राष्ट्र विरोधी कार्यों वाली धाराओं का उपयोग प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों, छात्रों, किसानों पर हो रहा है। लोकतंत्र की सेहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों का कारण बनती है। इस पर गंभीर बहस खड़ी हो गई है। छात्र, मजदूर, किसान, पत्रकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी जांच एजेंसियों के दमन और कठोर कानूनों की कार्रवाई से अछूता नहीं रहा। सरकारें चाहे केंद्र की हों या राज्यों की, सरकार के विरोध को फकानून-व्यवस्थाफ के स्थान पर अब राष्ट्र का विरोध मान लिया गया है। सरकार के निर्देश पर लंबे समय तक जेल में रखने की नीति जाँच एजेंसियाँ अपना रही हैं। इससे समाज के सभी वर्गों में असंतोष और सरकारों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। अब यह गुस्सा और अविश्वास कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी दिखने लगा है। अदालतें सरकार के दबाव में जमानत जैसे मामलों में कई महीने और सालों तक लटकाकर रख रही हैं। सारी विधि व्यवस्था को न्यायपालिका स्वयं नजर अंदाज कर रही है। ऐसी स्थिति में अब न्यायपालिका के ऊपर आम नागरिकों को वह विश्वास नहीं रहा, जो पहले होता था। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता है। नागरिकों को अपनी बात कहने, सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार से लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकारें नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के विरोध के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। पिछले कुछ वर्षों से आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराएं लगाकर साजिशन महीनों या वर्षों तक जेल में रखा जा रहा है। बाद में पर्याप्त सबूत न मिलने पर वर्षों बाद आरोपी अदालत से बरी हो जाते हैं। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कानून का उपयोग न्याय के लिए हो रहा है? सरकार से असहमति, आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का दुरूपयोग किया जा रहा है। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। लंबी हिरासत के बाद अदालतों में आरोपियों पर जो आरोप लगे थे, उससे संबंधित कोई तथ्य ही मुकदमे में नहीं था। अदालत में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे। उसके बाद भी इन मामलों में कोई रोक नहीं लगी। ईडी, सीबीआई, पुलिस इत्यादि जांच एजेंसियां गंभीर धाराओं में आरोपियों को बंद करके जाँच एवं पूछताछ के नाम पर कई महीनो तक जेल में बंद रखती हैं। आरोपियों का ट्रायल भी शुरू नहीं करती हैं। जांच भी कई वर्षों तक पूर्ण नहीं होती है। इससे युवाओं, छात्रों और श्रमिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के बीच यह भावना मजबूत हुई है, कानूनों का दुरूपयोग सत्ता के लिये किया जा रहा है। न्याय मिलने में देरी भी एक तरह की सजा है। फतारीख पर तारीखफ की व्यवस्था केवल अदालतों की प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि यह आम नागरिक की पीड़ा, प्रताणना और निराशा का प्रतीक बन चुकी है। पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के गुस्से को बढ़ाया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट एवं अन्य परीक्षाओं में जब गड़बड़ी हुई थी, तब ऐसे मामले पर विचार करने से मना कर दिया। जब परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों पर पुलिस कठोर कार्रवाई करती है। न्यायपालिका से जब न्याय नहीं मिलता है, तब व्यवस्था के प्रति आम नागरिकों का विरोध बढ़ता है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास, कानून व्यवस्था पर बनाए रखना भी है। नागरिकों के अधिकार और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना उनका पालन कराना, बिना किसी भेदभाव के और संवेदनशीलता के साथ नागरिकों के साथ व्यवहार करना होता है। इस पूरे परिदृश्य में न्यायपालिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ने अदालतों को नागरिको के मौलिक एवं कानूनी अधिकारों का संरक्षक बनाया है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय तक दांव पर लगी हो। विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद हो, झूठे आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो। तब न्यायपालिका से त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील हस्तक्षेप की अपेक्षा होती है। यदि जांच एजेंसियों की कार्रवाई में त्रुटियां हैं, जांच एजेंसियों ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया हैं। किसी दबाव में साजिश के साथ जाँच एजेंसी ने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, वह त्वरित कार्यवाही कर न्याय करे।

जापान की अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में 2.1 फीसदी की वार्षिक वृद्धि

पश्चिमी एशिया संघर्ष और ऊर्जा कीमतों की बढ़ोतरी के बावजूद दिखी मजबूती

टोक्यो ।

जापान की अर्थव्यवस्था ने जनवरी-मार्च तिमाही में 2.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से मजबूत वृद्धि दर्ज की है। पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद यह लगातार दूसरी तिमाही की वृद्धि देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाती है। मंत्रिमंडल कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इस बेहतर परिणाम का श्रेय मुख्य रूप से उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा बढ़ाए गए खर्च को जाता है। पिछले तिमाही के मुकाबले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.5 प्रतिशत की बढ़त हुई। निजी उपभोग में तिमाही आधार पर 0.3 प्रतिशत और सार्वजनिक मांग में भी 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान निर्यात में 1.7 प्रतिशत और आयात में 0.5 प्रतिशत की बढ़त हुई। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने भविष्य में इस विकास दर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिसके लिए सरकारी खर्च में और बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है।

अमेरिकी न्याय विभाग से अडानी को बड़ी राहत, आपराधिक मामले बंद

न्यूयॉर्क में चल रहे सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड के मामले को अदालत ने खारिज किए

नई दिल्ली ।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। न्यूयॉर्क में चल रहे सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड के मामले को अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह फैसला अडानी ग्रुप से जुड़े अमेरिका के कई प्रमुख कानूनी और नियामक मामलों का पटाक्षेप करता है, जिससे समूह को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला उन आरोपों के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी ग्रुप पर भारत में सौर परियोजनाओं के लिए कथित रिश्वत योजना और अमेरिकी निवेशकों से जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। समूह ने इन आरोपों को हमेशा बेबुनियाद बताया था। अमेरिकी अदालत में दाखिल दस्तावेजों में, न्याय विभाग ने आगे संसाधन खर्च न करने की बात कही, जिसके बाद अदालत ने मामले को`` विथ प्रेजू डिसीज खारिज कर दिया, यानी इसे भविष्य में दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। जांच में, अभियोजकों को आरोपों के पर्याप्त सबूत या स्पष्ट अमेरिकी कनेक्शन नहीं मिले, जिसके बाद डीओजे ने केस वापस लिया। अडानी के वकीलों ने अदालत में मजबूत कानूनी दलीलें दी थीं। हाल ही में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी गौतम अडानी और सागर अडानी के साथ सिविल सेटलमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बिना गलती स्वीकार किए भुगतान पर सहमति जताई। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओफेक एजेंसी ने भी ईरान से एलपीजी आयात से जुड़े प्रतिबंध उल्लंघन मामले को अडानी ग्रुप के 27.5 करोड़ डॉलर के भुगतान और सहयोग के वादे के साथ निपटाया था। कानूनी विशेषज्ञों और अडानी के वकीलों ने अमेरिकी कानूनों को भारतीय लेनदेन पर लागू करने के प्रयासों पर सवाल उठाए थे, यह तर्क देते हुए कि बॉन्ड्स अमेरिकी एक्सचेंजों पर ट्रेड नहीं होते थे और निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद, अडानी ग्रुप को मिली यह कानूनी और कारोबारी राहत उसके वैश्विक विस्तार योजनाओं और निवेशकों के भरोसे को मजबूती प्रदान कर सकती है।

बैंकों की बंपर कमाई फिर भी कमजोर मूल्यांकन, बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड गिरावट

निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी 43.5 फीसदी कम मूल्यांकन पर

नई दिल्ली ।

बाजार के मौजूदा हालात में बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि और कमाई निवेशकों को चिंतित कर रही है। बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचकांक के मुकाबले बैंक निफ्टी का मूल्यांकन रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो 2015 के बाद सबसे बड़ा अंतर है। यह तब हो रहा है जब बैंकिंग क्षेत्र ने बीते कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट आय वृद्धि में अहम योगदान दिया है। बैंक निफ्टी वर्तमान में निफ्टी 50 की तुलना में 43.5 फीसदी कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। इसका प्राइस-टु-बुक अनुपात 1.83 है, जबकि निफ्टी 50 का 3.25। खास बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में बैंक निफ्टी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) में 172 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि हुई।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 114 , निफ्टी 31 अंक गिरा

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हल्की गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बिकवाली हावी रहने से आई है। आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला पर बाजार बंद होने से कुछ ही समय पहले इसमें गिरावट आने लगी । अंतिम घंटे में बैंक, वित्तीय और धातु शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 114.19 अंक टूटकर 75,200.85 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31.95 अंक फिसलकर 23,618 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। कोटक महिंद्रा के अलावा टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स, इंडिगो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस के शेयरों भी गिरावट रही जबकि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस के शेयर उछले। निफ्टी पर टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिडकैप में 0.91 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप में 1.17 फीसदी बढ़त रही। वहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट आई। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर भी गिरे। निफ्टी आईटी, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी केमिकल में भी तेजी रही। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला। सुबह निफ्टी 87 अंक की बढ़त के साथ 23,726.6 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह, सेंसेक्स भी 320.09 अंक की तेजी के साथ 75,651.53 पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य पश्चिम एशियाई देशों के अनुरोध के बाद एक प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्षेत्र में ऐसा समझौता संभव है ।

आईओसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 56 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली ।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 56 प्रतिशत बढ़कर 11,377.51 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आईओसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चौथी में उसका एकल आधार पर मुनाफा बढ़कर 11,377.51 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024-25 की समान तिमाही में 7,264.85 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा कि इस तिमाही में उसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने के कारण भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का मुनाफा 36,802.42 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 12,961.57 करोड़ रुपये था।

ईरान पर अमेरिकी हमला टलते ही कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमला टालने की घोषणा से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स मंगलवार को 2.55फीसदी गिरकर 109.194 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.91फीसदी टूटकर 102 डॉलर प्रति बैरल हो गया। सोमवार को यूएई के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए ड्रोन हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत दो सप्ताह के उच्चतर पर पहुंच गई थी। अब क्रूड की कीमतों में आई गिरावट भारत समेत दुनिया के लिए बड़ी राहत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यह हमला पूरी तरह तय था, लेकिन मिडिल ईस्ट के तीन सबसे शक्तिशाली और बड़े नेताओं के सीधे हस्तक्षेप और व्यक्तिगत अनुरोध के बाद उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले रोकने के निर्देश दिए हैं। तेल बाजार इस समय अमेरिका और ईरान के तनाव पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। शांति समझौते की दिशा में थोड़ी सी प्रगति होने पर क्रूड के दाम गिर जाते हैं तो तनाव बढ़ने के संकेत मिलते ही ऊपर चढ़ जाते हैं। होर्मुज खुलेगा या नहीं, यह इसी समझौते पर निर्भर है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी से शुरू किए गए हमलों के जवाब में रणनीतिक महत्व वाले इस जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी समुद्री तेल पर लागू प्रतिबंधों में दी गई अस्थायी छूट को 30 दिन के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों ने अमेरिका से आग्रह किया था कि उन्हें रूसी तेल खरीद जारी रखने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए। अमेरिका ने पहले यह छूट मार्च में दी थी ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कमी और कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित किया जा सके।

प्रवर्तकों के पूंजी निवेश से मजबूत हुआ वीआई का इरादा, जल्द बैंक कर्ज मिलने की उम्मीद

35,000 करोड़ रुपये की फंडिंग के लिए बैंकों से बातचीत अंतिम दौर में

नई दिल्ली ।

देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआई) का शीर्ष प्रबंधन बैंकों से 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी डालने के फैसले और 5जी नेटवर्क के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। कंपनी जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद अपनी रणनीति पर खुलकर बात की। वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्य अधिकारी अभिजित किशोर ने बताया कि कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह, जिसमें सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक शामिल हैं, के साथ 35,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और 10,000 करोड़ रुपए की गैर-वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा शामिल होगी। किशोर ने बातचीत पूरी होने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन जल्द सफल होने का भरोसा जताया। यह भरोसा ऐसे समय में आया है जब आदित्य बिड़ला समूह ने तरजीही निर्गम के जरिये वीआई में 4,730 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। इसमें सिंगापुर की कंपनी सूर्यजा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को वारंट जारी किए जाएंगे, जिसकी लगभग 25 फीसदी रकम तुरंत चुकाई जाएगी और शेष 18 महीनों में। इस निवेश से प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 3.82 फीसदी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि कुमार मंगलम बिड़ला को इसी महीने वोडाफोन आइडिया का गैर-

कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वीआई अगले तीन वर्षों में 5जी नेटवर्क शुरू करने और अपनी बाजार स्थिति मजबूत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही है।

कंपनी का लक्ष्य दो अंकों में आय वृद्धि, परिचालन मुनाफे को तीन गुना करना और ग्राहकों को लगातार जोड़ते रहना है। अभिजित किशोर ने निदेशक मंडल में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि ये कदम प्रवर्तक समूह के दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को पिछले साल दिसंबर में संशोधित आकस्मिक देनदारी समायोजन तंत्र (क्लैम) समझौते के तहत वोडाफोन पीएलसी से 5,836 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, जिसकी मूल संधि 2017 में विलय के दौरान हुई थी।

अदाणी मामला सुलझने से भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को मिलेगा बल यूएसआईएसपीएफ

रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी

वॉशिंगटन ।

अदाणी एंटरप्राइज से जुड़े कानूनी विवाद के अमेरिकी न्याय मंत्रालय के साथ निपटारे से भारत-अमेरिका की मजबूत आर्थिक साझेदारी में आ रही एक बड़ी बाधा समाप्त हो गई है। यूएसआईएसपीएफ (अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच) ने इस समाधान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी। समूह ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों के निपटारे के लिए 27.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है, जिसके बाद उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप स्थायी रूप से वापस ले लिए गए हैं।

यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि अदाणी एंटरप्राइज का अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने का संकल्प राजदूत सर्जियो गोर की उस हालिया घोषणा पर आधारित है, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों में 20.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही हैं। यूएसआईएसपीएफ का मानना है कि ये निवेश अमेरिका में मजबूत भागीदार बनने की भारतीय कंपनियों की इच्छा को दर्शाते हैं। इससे मौजूदा सहयोग को बल मिलेगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और दीर्घकालिक द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति

नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने भी जांच में अदाणी समूह के व्यापक सहयोग और सक्रिय रूप से जानकारी साझा करने की सराहना की। इस निपटारे से न्यूयॉर्क में चल रहा प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी का चर्चित मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है।

भीषण गर्मी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग

विद्युत मंत्रालय ने गर्मी में 270 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया

नई दिल्ली । देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके चलते बिजली की मांग ने सोमवार को सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया। एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर जैसे शीतलन उपकरणों के व्यापक उपयोग के कारण अधिकतम बिजली मांग 257.37 गीगावाट दर्ज की गई, जो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। विद्युत मंत्रालय ने हालांकि पुष्टि की है कि इस पूरी मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद यह रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई, जो 256.11 गीगावाट के पिछले उच्च स्तर से अधिक है। मंत्रालय का अनुमान है कि इस गर्मी में देश की अधिकतम बिजली मांग 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में लू चलने का अनुमान लगाया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 24 मई तक लू की आशंका है, जबकि उत्तर प्रदेश में भीषण लू की स्थिति बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा शीतलन उपकरणों के बढ़ते उपयोग से बिजली की मांग एवं खपत आगे भी बढ़ सकती है। आईएमडी ने इस वर्ष भीषण गर्मी रहने का अनुमान जताया है।

देश का खाद्य तेल आयात 2025-26 में तीन प्रतिशत बढ़ा उद्योग निकाय

एसएएफटीए समझौते के तहत नेपाल से 113 फीसदी की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज

नई दिल्ली।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का खाद्य तेल आयात तीन प्रतिशत बढ़कर 166.51 लाख टन तक पहुंच गया है। उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने बताया कि नेपाल से शुल्क-मुक्त आयात में हुई भारी वृद्धि इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण रही, जिसने पिछले वर्ष के 161.82 लाख टन के आंकड़े को पार कर लिया। एसईए के अनुसार दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के तहत शून्य-शुल्क पहुंच का लाभ उठाते हुए नेपाल ने इस अवधि में भारत को 7.36 लाख टन खाद्य तेल निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 3.45 लाख टन से 113 प्रतिशत अधिक है। नेपाल से परिष्कृत सोयाबीन तेल का सबसे अधिक आयात हुआ, जिसने कुल आयात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि एसएएफटीए व्यवस्था न होती तो आयात पिछले स्तर से कम रह सकता था। भारत अब भी अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। तिलहन की कम पैदावार, खंडित

भूमि जोत, सीमित सिंचाई और गेहूं-चावल केंद्रित कृषि नीति घरेलू उत्पादन में बाधा डाल रही है। एसईए ने दीर्घकालिक आयात निर्भरता घटाने के लिए तिलहन उत्पादकता बढ़ाने और घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाद्य तेल उपभोग को नियंत्रित करने की हालिया अपील का जिक्र करते हुए एसईए ने कहा कि घरेलू उत्पादन वृद्धि और अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण से आयात निर्भरता कम होगी तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा।

बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सरकार समर्थित इस योजना में 8.2 फीसदी तक ब्याज और हर तिमाही मिलती है निश्चित आय

नई दिल्ली ।

रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा हर व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक बेहद भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरी है। यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें और नियमित आय का आनंद ले सकें। एससीएसएस को भारत सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है, जिससे इसमें निवेश किया गया पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और जोखिम लगभग शून्य हो जाता है। वर्तमान में, यह योजना सालाना 8.2 फीसदी की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार निवेश करने के बाद यह ब्याज दर पूरी 5 साल की अवधि के लिए तय रहती है, भले ही भविष्य में बाजार दरों में उतार-चढ़ाव आए। ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में सीधे निवेशक के खाते में किया जाता है, जिससे नियमित आय सुनिश्चित होती है। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। व्यक्तिगत खाते के लिए अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपए और जॉइंट खाते के लिए 30 लाख रुपए है। सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें खाता खोल सकते हैं, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में 50 या 55 वर्ष से अधिक आयु के रिटायर्ड कर्मी भी पात्र होते हैं। योजना की अवधि 5 साल है, जिसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। जो लोग अधिकतम निवेश का विकल्प चुनते हैं, उन्हें इसका अच्छा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक एससीएसएस में अधिकतम 30 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से उन्हें लगभग 2,46,000 रुपए प्रति वर्ष का ब्याज मिलता है। यह राशि तिमाही आधार पर लगभग 61,500 रुपए होती है, जिसका अर्थ है कि निवेशक को औसतन लगभग 20,500 रुपए प्रतिमाह की नियमित और निश्चित आय प्राप्त होती है। यह स्कीम बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता और मन की शांति प्रदान करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है।

वैश्विक तनाव से क्रिप्टो बाजार में खलबली, बिटकॉइन मई के निचले स्तर पर

ईरान-अमेरिका तनाव और ईटीएफ से निकासी का दिखा असर, एशियाई बाजारों में भी गिरावट

वाशिंगटन ।

अमेरिका और ईरान के बीच गहराते तनाव तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने क्रिप्टो बाजार में भूचाल ला दिया। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन मई महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर गिरकर 76,568 डॉलर पर आ गई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई।

वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सोमवार को बिटकॉइन ने मई महीने का अपना सबसे निचला स्तर छू लिया। 76,568 डॉलर तक गिरने के बाद, खबर लिखे जाने तक यह 1.42 फीसदी की गिरावट के साथ 77,256 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

एथेरियम और सोलाना जैसी प्रमुख डिजिटल संपत्तियों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि एशियाई बाजार खुलने के शुरुआती 15 मिनट में लगभग 50 करोड़ डॉलर के लॉन्ग पोजिशन खत्म हो गए। जार में यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका-ईरान तनाव से पैदा हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण आई।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को चेतावनी भरे बयान और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर

बनी आशंकाओं ने निवेशकों को जोखिम वाले निवेश से दूर कर दिया। इसके साथ ही, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से पिछले सप्ताह 1 अरब डॉलर से अधिक की रिकॉर्ड निकासी ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया, जो जनवरी के बाद पहली बार हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में भी करीब 3 फीसदी की तेजी आई, और अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 111.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

विश्लेषकों के अनुसार बिटकॉइन के लिए 75,000-73,000 डॉलर का स्तर मजबूत सपोर्ट है, जबकि 77,000 डॉलर तत्काल रेजिस्टेंस माना जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को अचानक आने वाली तेजी के पीछे भागने के बजाय पोर्टफोलियो संतुलन और मजबूत बुनियादी आधार वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर दिखा, जहां जापान का निक्केई 225 और हांग सेंग इंडेक्स लगभग 1 फीसदी गिरे।

सरकार ने मंदिर के सोने के मुद्रीकरण की अफवाहों को खारिज किया

वित्त मंत्रालय ने कहा- नागरिकों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील

नई दिल्ली।

सरकार ने देशभर के मंदिरों के पास रखे सोने के मुद्रीकरण को लेकर चल रही अफवाहों और अटकलों को मंगलवार को सिरे से खारिज कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी, भ्रामक और निराधार हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिरों के शिखरों या दरवाजों पर लगे सोने को भारत के सामरिक स्वर्ण भंडार के रूप में मानने के दावे भी झूठे और निराधार हैं। सरकार ने नागरिकों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने और उन्हें न फैलाने की अपील की है, क्योंकि इससे अनावश्यक भ्रम फैलता है। मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा कि

सभी महत्वपूर्ण जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों जैसे प्रेस विज्ञप्तियों और सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से ही जारी की जाएगी, इसलिए केवल उन्हीं पर भरोसा किया जाए।

पीएम मोदी यात्रा के अंतिम चरण में इटली के संबंधों को देंगे मजबूती

मेलोनी से मुलाकात में इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खास ध्यान

रोम।

पीएम नरेंद्र मोदी 19-20 मई को यात्रा के अंतिम चरण में इटली के दौरे पर हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद पीएम मोदी की पहली अहम यूरोपीय यात्रा है। इस समय वैश्विक चुनौतियों, जैसे पश्चिम एशिया संकट और सप्लाई चेन में पैदा हुए दिक्कतों के बीच इस दौरे को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। यह दौरा दोनों देशों के बीच 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' को लागू करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह पंचवर्षीय कार्य योजना द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का एक व्यापक रोडमैप है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इटली के संबंध हमेशा इतने मजबूत नहीं रहे। साल 2010 के दशक में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड पर भारत में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद भारत ने कंपनी पर बैनन लगा दिया था और रक्षा सहयोग ठप पड़ गया था।

इसी दौरान इतालवी मरीन विवाद ने भी संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। कई सालों तक दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक और नई सैन्य डील्स को लेकर समझौतों की कमी बनी रही। हालांकि बाद में कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर हालात सुधरने लगे। साल 2021-22 के बाद संबंधों में तेजी से सुधार आया है। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यहां साल 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 16.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। 2000 से 2025 के बीच भारत को इटली से 3.66 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

अपनी यात्रा में पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्टारेला और पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन मुलाकातों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग, संयुक्त रक्षा उत्पादन, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी।

तमिलनाडु के सीएम विजय ने लिट्टे के पूर्व चीफ प्रभाकरन को दी श्रद्धांजलि

कहा- हम मुल्लीवाइकल की यादों को हमेशा दिलों में संजोकर रखेंगे

चेन्नई।

तमिलनाडु सीएम सी जोसेफ विजय ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के पूर्व चीफ को प्रभाकरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के चीफ ने श्रीलंका की मुल्लीवाइकल का जिक्र करते हुए कहा कि हम मुल्लीवाइकल की यादों को हमेशा दिलों में संजोकर रखेंगे। विजय ने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा- हम हमेशा समुद्र के उस पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। गौरतलब कि जिस लिट्टे चीफ को विजय श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसे भारत में पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के आरोप में बैन कर दिया गया था। इस हत्याकांड में प्रभाकरन भी आरोपी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका से अलग देश की मांग करने के लिए बने संगठन लिट्टे के चीफ प्रभाकरन की पुण्यतिथि की याद में श्रीलंकाई और भारतीय तमिल समुदाय इसे तमिल नरसंहार स्मरण दिवस या मुल्लीवाइकल स्मरण दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन उन हजारों तमिल नागरिकों को याद किया जाता है, जो मुल्लीवाइकल में हुए सैन्य अभियान के दौरान मारे गए थे। 18 मई 2009 को मुल्लीवाइकल में ही श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरन को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद तीन दशक पुराना श्रीलंकाई गृहयुद्ध खत्म हो गया था। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस गृहयुद्ध में 40,000 से लेकर 70,000 तमिल नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी।

बता दें यह पहली बार नहीं है, जब विजय ने प्रभाकरन को याद किया हो। इससे पहले भी उन्होंने 2025 में एक रैली के दौरान अपने भाषण में प्रभाकरन का जिक्र किया था। इस दौरान भी विजय ने कहा था कि वह समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर में नशा बना चुनौती, आतंकवाद-नशे का आपस में संबंध

एलजी सिन्हा का दावा- आतंकी गतिविधियां खत्म, भर्ती न के बराबर

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के दावे के साथ नशे की चुनौती को बड़ा संकट बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नशे का आपस में संबंध है। नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हमारा ध्यान जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है। आतंकी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई हैं और आतंकी भर्ती भी न के बराबर है। सुरक्षाबलों ने घाटी में सक्रिय सभी आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बीएसएफ और सेना के जवान इन्हें विफल कर रहे हैं।

पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मारा गया है और उनके मददगार पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां साइबर जिहादियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। नशा मुक्त अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। पुलिस ने पिछले 38 दिन में 766 एफआइआर दर्ज की हैं, 856 लोगों को गिरफ्तार किया है और 677 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है।

श्रीनगर गढ़वाल में गहराया ईंधन संकट: पेट्रोल-डीजल के लिए भटक रहे यात्री

देहरादून ।

श्रीनगर गढ़वाल इन दिनों भीषण ईंधन संकट का सामना कर रहा है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल समाप्त होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां से गुजरने वाले हजारों तीर्थयात्रियों के साथ-साथ लोकल वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ईंधन न मिलने के कारण कई वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर शाम से ही जीएमओयू पेट्रोल पंप और श्रीकोट स्थित दोनों पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो चुका है। इसके बाद अब केवल इक्का-दुक्का पंपों पर ही सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध है। एनआईटी स्थित पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के लिए सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। शहर से करीब चार किलोमीटर दूर स्थित जिंथो पेट्रोल पंप पर भी फिलहाल कुछ स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन यहां भी वाहनों की भारी भीड़ के चलते जल्द ही ईंधन खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। ईंधन की किल्लत के चलते चारधाम यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मीलों दूर दूसरे कस्बों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उनकी यात्रा और भी दुष्कर हो गई है।

स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रहे हैं, जिससे आम जनता में गहरा रोष है। यह संकट अगर जल्द हल नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

पालघर में भीषण सड़क हादसे में 13 की मौत, 25 घायल

शादी की खुशियां मातम में बदली, तेज रफ्तार कंटेनर ने टेम्पो को मारी टक्कर

मुंबई।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दहनू के धनिवारी इलाके में बारात लेकर जा रहा एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात टेम्पो बापूगांव से धनिवारी की ओर सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था। बताया जा रहा है कि चालक ने लंबा रास्ता बचाने के लिए वाहन को गलत दिशा में मोड़ दिया। इसी दौरान गुजरात से मुंबई की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर टेम्पो पर पलट गया।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो में सवार कई लोग मौके पर ही दब गए। हादसे के समय वाहन में 50 से ज्यादा बाराती सवार थे।

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

होर्मुज से आई अच्छी खबर, 55 मालवाहक जहाज गुजरे इसमें तेल-गैस के टैंकर भी

रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाल में ज्यादा जहाज इस मार्ग से गुजरने की दी अनुमति

नई दिल्ली।

ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में तेल-गैस के बढ़ते हुए दाम को लेकर हाहाकार मचा है। यहां तक कि भारत में भी लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से खुशखबरी मिली है कि हफ्तेभर में यहां से शिप्स की सबसे बड़ी संख्या गुजरी है। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। समुद्री निगरानी कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक 11 मई से 17 मई के बीच हर सप्ताह करीब 55 मालवाहक जहाज इस रास्ते से गुजरे। इससे पहले युद्ध के दौरान यह संख्या गिरकर सिर्फ 19 जहाज रह गई थी, जो संघर्ष शुरू होने के बाद का सबसे निचला स्तर था।

बता दें 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल ने संयुक्त रुप से ईरान पर किए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया था। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल और गैस बाजारों में भारी उथल-पुथल मच गई थी।

जहाजों की आवाजाही रुकने से दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि समुद्री यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाल के दिनों में ज्यादा जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी है।

रिपोर्ट में कहा गया कि सप्ताह की शुरुआत में एक ही दिन में 30 से ज्यादा जहाजों को मंजूरी दी गई। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं और युद्ध से पहले जैसी स्थिति लौटने में समय लगेगा। पिछले सप्ताह गुजरने वाले 55 जहाजों में अलग-अलग प्रकार के मालवाहक पोत शामिल थे। इनमें करीब आधे तेल और अन्य तरल पदार्थ ले जाने वाले टैंकर थे। इसमें तीन बड़े क्रूड ऑयल टैंकर चीन, ओमान और जापान की ओर जा रहे थे। इसके अलावा 15 ड्राई बल्क जहाज और 16 एलपीजी टैंकर भी इस रास्ते से गुजरे।

केदारनाथ यात्रा में घायल हुए मुंबई के श्रद्धालु, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान

रुद्रप्रयाग।

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चिरबासा हेलिपैड के समीप एक यात्री घायल हो गया, जिसके बाद डीडीआरएफ और वाईएमएफ की रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए सफल बचाव अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार, मुंबई निवासी 63 वर्षीय सत्यनारायण स्वामी गौरीकुंड से पैदल केदारनाथ जा रहे थे। यात्रा के दौरान पोल नंबर 81 के पास अचानक चक्कर आने से वह रास्ते पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर और नाक पर चोट लग गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल यात्री को स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और उनकी स्थिति सामान्य बताई। प्रशासन ने यात्रियों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर तुरंत सहायता लेने की अपील की है।

किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑटो-टैक्सी हड़ताल का ऐलान

वाहन चालक यूनियनों ने दी दिल्ली में 21 से 23 मई तक 'चक्का जाम' की चेतावनी

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। ऑटो और टैक्सी चालक यूनियनों ने किराये में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 21, 22 और 23 मई को तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। 'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भेजकर अपनी मांगें रखी है। यूनियनों का कहना है कि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने चालकों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। 'चालक शक्ति यूनियन' के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा कि बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण चालक अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द किराया संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं करती, तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। यूनियनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी किराए में पिछले करीब 15 वर्षों से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं। ऐप-आधारित कैब कंपनियों पर भी मनमाने किराए और ड्राइवरों के शोषण के आरोप लगाए गए हैं। 23 मई को दिल्ली सचिवालय पर संयुक्त प्रदर्शन की भी घोषणा की गई है।

मामूली विवाद पर पति ने की पत्नी और तीन बच्चों की हत्या

आरोपी ने खुद को भी किया घायल, पुलिस कर रही जांच

दरभंगा।

बिहार के दरभंगा में एक युवक ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह चंदनपट्टी में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद पति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि यह परिवार बंगाल से आकर यहां किराये के मकान में रह रहा था। आरोपी पति के बारे में बताया जा रहा है कि पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के बाद उसने खुद को भी घायल कर लिया है। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृत पत्नी की पहचान बंगाल के दालकोला जिले के कुंडी थाना क्षेत्र के निवासी संदीप दास की पत्नी फूल कुमारी दास (30) और बच्चे हृदय दास (7), संध्या दास (6) और पांच साल का मासूम सोन दास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आरोपी युवक चंदनपट्टी स्थित एक मुर्गा फार्म में मजदूरी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मृत बच्चों के मामा ने बताया कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी में सुबह विवाद हुआ था। इसके बाद डंडा, रॉड आदि से पीट-पीटकर संदीप ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। फिर खुद को भी घायल कर लिया। इधर पतोर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और जांच शुरू की। मुर्गी फॉर्म में काम करने वाली सुनीता दास के मुताबिक मजदूर बिल्टू दास उर्फ संदीप दास ने पत्नी व तीनों बच्चों के साथ सुबह कमरे में बुरी तरह मारपीट की। उस समय अन्य मजदूर मुर्गियों को दाना-पानी दे रहे थे। एक बच्चे ने हल्ला सुनकर सभी मजदूरों को सूचित किया। जब सभी जुटे तो देखा कि चारों बुरी तरह घायल हैं। बिल्टू दास का भी सर फटा हुआ था।

देश के 18 शहरों में शुरू होगी वाटर मेट्रो

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने देश में जल-आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति तैयार की है। इस योजना के तहत देश के 18 शहरों में चरणबद्ध तरीके से वाटर मेट्रो सेवा शुरू किए जाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क यातायात पर दबाव कम करना, प्रदूषण घटाना, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। नीति में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड नौकाओं के उपयोग, आधुनिक टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। कोच्ची की वाटर मेट्रो परियोजना की सफलता को मॉडल बनाकर अन्य शहरों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। इससे पर्यटन, रोजगार और शहरी कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है।

झारखंड में करोड़ों का वेतन घोटाला: एसआईटी ने फ्रीज किए सैकड़ों बैंक खाते, जांच में तेजी

रांची।

झारखंड में जिलों के कोषागार से करोड़ों रुपये के अवैध वेतन निकासी घोटाले की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अब तक बोकारो और हजारीबाग जिलों के 850 बैंक खातों की जानकारी जुटाई है, जिन्हें जांच के दायरे में लिया गया है। इसमें बोकारो के 600 और हजारीबाग के 250 बैंक खाते शामिल हैं। जांच के दौरान जैसे-जैसे सरकारी खातों से हुई अवैध निकासी के मामले उजागर हो रहे हैं, एसआईटी तेजी से संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करा रही है। अब तक बड़ी संख्या में संदिग्ध खातों को फ्रीज किया जा चुका है। इतना ही नहीं एसआईटी ने खाताधारकों को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है, जिनसे उनके खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन का संतोषजनक जवाब मांगा जा रहा है। जिन खाताधारकों से उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा, उनके खातों को तत्काल फ्रीज किया जा रहा है। अब तक की जांच में हजारीबाग में करीब 31 करोड़ रुपये और बोकारो में 11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है, जो कुल 42 करोड़ से अधिक का घोटाला है। एसआईटी अब पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपितों को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ करेगी। इसी क्रम में बोकारो एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में पदस्थापित सिपाही कौशल पांडेय से रिमांड पर पूछताछ की जानी है। एसआईटी कौशल पांडेय के सहयोगियों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों तक पहुंचने के लिए भी जानकारी जुटाएगी, ताकि घोटाले के सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717